उत्तर प्रदेश अव्वल प्रदेश

जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16 प्रतिशत से अधिक कामकाजी वर्ग हो, 5 लाख से अधिक आबादी वाले एक दर्जन से अधिक शहर हों, हर जिले का अपना कोई न कोई खास उत्पाद हो, बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां हों, लघु उद्योग हों, गंगा-यमुना-सरयू सरीखे अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे उत्तर प्रदेश को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। उत्तर प्रदेश की पहचान आधुनिक रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के संगम के रूप में भी होने वाली है। ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी में दो आयामों में जुड़ने वाले हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले हैं। वेस्टर्न नोएडा क्षेत्र व यमुनानगर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुपरपोर्ट हब का निर्माण भी हो रहा है। इन्डस्ट्रियल स्टेट्स और लॉजिस्टिक के विकास से पूर्वी देश के माथे से आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। यहां बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, बढ़ता निवेश अनेक नये अवसर लेकर आ रहा है।

–नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

मिशन रोज़गार

प्रदेश के विकास, गरीबों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। युवाओं को विभिन्न विभागों में न केवल सरकारी नौकरी बल्कि प्रदेश में भारी निवेश आकर्षित कर रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सरकार नयी एमएसएमई नीति, ओडीओपी नीति और आईटी नीति के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास कर रही है। रोजगारपरक योजनाओं के लिए उद्यमियों को भी कई तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ चल रही योगी सरकार प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के औद्योगिक विकास और दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से सरकार अगले साल फरवरी में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी। इसमें दुनियाभर के नामचीन उद्योगपति शामिल होंगे।

केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, वह आज सार्थक परिणाम दे रहे हैं। सरकार की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या गिरे निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे अन्य सकल क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करना, हर क्षेत्र में अभिनव प्रयोग हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल को तत्काल कर उस पर काम किया जा रहा है। इससे निवेश और रोजगार के मौके बढ़े हैं। विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। माफिया और घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बन रहा है।

–योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

बढ़ते निवेश से तेज हुई यूपी की रफ्तार

अतुलरंजन सिंह

योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर चुकी है। सरकार ने इस अवधि में अपने कई संकल्पों को जमीन पर उतार दिया है। युवाओं के रोजगार की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लगातार बनाने की कुलांचें हों या दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, हर मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर : विकास को मिली गति

[illegible]

[illegible]

निवेश को लगे पंख

[illegible]

- प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की उद्योगधंधा बनाने के लिए सरल सरकार उपलब्धता उपलब्धता है
- मुख्य प्रोत्साहन, निवेश, बनाए और मार्केटिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए राज्य इन्क्यूबेटर्स और नेक्स्ट जेनरेशनइन्क्यूबेटर का हो जाने
- 2020 में राज्यपालीय नवीकरण इन्वेस्टर समिट में पहले प्रदेश में नीतियां अधिकारियों से निवेशकों को आकर्षित करना रहा है
- बिजनेस में सुगमता रैंकिंग रोलिंग के पहले 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से लोकनिर्माण कार्य कराना

उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने में 17 राज्यों को पीछे छोड़ा

- 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5 फीसदी थी जो अब घटकर 2.7 फीसदी रह गयी है

[illegible]

रोजगार देने में आगे

[illegible]

5.26 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 2.75 करोड़ को रोजगार

[illegible]

निवेश सपनों जा रहे पूरा

[illegible]

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल सेल में एक महिला को बालाजी का चेक प्रदान करते हुए

सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ने आसान किया विकास का रास्ता

[illegible]

योगी सरकार की नीतियों पर मुहर

24 से ज्यादा देशों ने किया 50 हजार करोड़ का निवेश

अतुल सिंह

[illegible]

26371	39
करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव 12 देशों से मिले हैं	परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है

38 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा

प्रमुख निवेशक देशों जैसे सिंगापुर, सूरीनाम, जकार्ता, सूडान, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां

सरकार पर बढ़ता भरोसा, प्रदेश में बढ़ता निवेश

[illegible]

मोबाइल फोन निर्माण में अग्रणी

- भारत में निर्मित होने वाले मोबाइल फोन में से 45 फीसदी उत्तर प्रदेश से भेजे हैं।
- देश के सूक्ष्म मोबाइल कम्पोनेन्ट्स में भी 55 फीसदी का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा है।
- 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने सहित देश का पहला राज्य बनने की ओर पूर्वी (मथुरा एक्सप्रेस-वे आसपास इलाके से पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 100 एकड़ क्षेत्र में बना रही है)

नोएडा में बिना की सभी बड़ी मोबाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन करते पीएम नरेंद्र मोदी

एयर कनेक्टिविटी में तेजी से बढ़ रहे यूपी के कदम

- प्रदेश में इस समय 9 हवाई अड्डे- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बुंदेलखंड और कुशीनगर में संचालित हैं
- इन में हवाई अड्डों के 60 गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क उपलब्ध है
- राज्य में जल ही 3 जलहवाईअड्डे हवाई अड्डे होंगे, इनमें अयोध्या का जलहवाईअड्डे हवाई अड्डा भी होगा
- पहला हवाईजहाज एकमात्र नैनी होने के साथ ही देश का पहला यूनिक हब बनाया जायेगा
- मिर्जापुर, जेवरगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और आगरा में अपने तरह का एयरोसिटी स्थापित किये जाने हैं

बुंदेलखंड एयरपोर्ट

खास-खास बढ़ रहा बैठी ट्रेन का दायरा

- लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, देहरादून और कानपुर के बीच का अन्य संपर्क
- आगरा में 25.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण (निर्माण के साथ के पूर्वी हिस्से तक 54 किलोमीटर का कॉरिडोर 1 जून आगरा मेट्रो में कॉरिडोर निर्माण तक 15.4 किलोमीटर का कॉरिडोर 2 है)
- वाराणसी में मेट्रो के लिए जल्द जल रोड्स, प्रोजेक्ट प्रगति पर है।

वाराणसी मेट्रो

आईटी सेक्टर की तेज रफ्तार, बढ़ते रोजगार

- आईटी सेक्टर में निवेश से 2017 से 2022 तक 43760 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव
- नोएडा, आईआईटी कानपुर, एमएमडीए लखनऊ में मेट्रो ऑफ सुपरमोड बनाने रहे
- अनुसंधान विकास केन्द्र, एलोरेन्स प्रौद्योगिकी पार्क और इस तरह एक ई. लखनऊ सुविधा केन्द्र भी बनाये जा रहे हैं
- लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ में आईटी पार्क निर्माणाधीन, बीटी में भी आईटी पार्क बनाये जाएंगे
- आईटी सिटी लखनऊ के साथ मुख्य और राज्यों में आईटी केन्द्र स्थापित करने की योजना

4 डाटा सेंटर का यूपी में हो रहा निर्माण

ये कंपनियां कर रही डाटा सेंटर में निवेश

रिलायंस इंडस्ट्रीज	9,134.30 करोड़ रुपये
अडानी इंटरप्राइजेज	5,126 करोड़ रुपये
टिकी इंडिया	2,700 करोड़ रुपये
कायनस इंफ्रास्ट्रक्चर	2,414 करोड़ रुपये
ग्लोबिटी लॉजिक	1,687 करोड़ रुपये

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश

मैसिक इंडस्ट्रीज	175
सेमसंग	200
रिलायंस रिलायंसीजी	270
फॉक्सकॉन	371
डेल	1,400
मल्लकोड	1,500
इंटेलिक	2,000
एप्पलप्रोसेसिंग	2,200
वीवो	7,000
सेमसंग	8,000
ओपो	8,000

अरबों करोड़ रुपये में

ओडीओपी : मिले लाखों रोजगार, निर्यात को लगे पंख

- ओडीओपी योजना से यूपी का निर्यात 62 फीसदी बढ़ा है। 2017-2018 में यहां आंकड़ा 28,967 करोड़ रुपये था, जो अब 1.56 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
- अपने यहां यहीं से ओडीओपी उत्पादों का निर्यात और निर्यात के मुख्य बाजारों के लिए उत्पादन की और से समाधान प्रदान किये जा रहे हैं।
- ई-कॉमर्स पोर्टल पर करीब 40 हजार ओडीओपी उत्पाद मौजूद हैं। जब कि 16 हजार करोड़ रुपये के उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल से बेचे जा चुके हैं।
- अब तक 7 लाख किसी का आवेदन कर 47 लाख से अधिक लाभार्थियों को 3.11 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं। इसमें 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।
- 1,347 करोड़ रुपये की प्रोत्साहनराशि को ओडीओपी की मुख्य बाजार के साथ ये निर्यातकों दिया गया है।
- 2000 लाभार्थियों को 20.14 लाख रुपये मार्जिन मनी वितरित की गयी है।
- 32,123 ओडीओपी लाभार्थी प्रोत्साहन दिये गये हैं और 28,173 को ओडीओपी पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।
- गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, आजमगढ़ व जनपद में मल्टीमॉडल कॉमन (सीएफसी) बनाकर किये जा चुके हैं, जबकि 23 सीएफसी पर काम चल रहा है। 11 सीएफसी के प्रस्ताव विचाराधीन चल रहे हैं।
- 20 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। ऐसे ही 29 नये उत्पादों के लिए जीआई टैग के आवेदन दिये जा चुके हैं।
- 3 ओडीओपी विकास कार्यालय, 21 ओडीओपी प्रोत्साहन, मुख्यालय केन्द्र, मुख्य सहित 100 से अधिक कार्यालयों में ओडीओपी प्रकोष्ठ गठन किये गये हैं।
- देश के सबसे सस्ते और अच्छे पोर्टल के रूपों का 75 फीसदी तक अनुदान प्रदान किया है।
- ओडीओपी मार्केटिंग सहयोग के लिए 25 लाख रुपये तक के लिए 75 फीसदी तक अनुदान की व्यवस्था, 1.5 करोड़ रुपये तक के लिए 50 फीसदी 10 प्रतिशत है।
- ओडीए 'वैल्यू' ओडीओपी उत्पाद एवं कारीगर का विपणनपत्र एवं व्यापार वैल्यू, पोस्टमुख्य की व्यवस्थित।

80% वृद्धि हुई यूपी के निर्यात में

1.56 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुका है कुल निर्यात

(2017-18 में यह आंकड़ा 28,967 करोड़ रुपये था)

25 लाख लोगों को ओडीओपी के माध्यम से रोजगार

लोकल को ग्लोबल बनाने की तैयारी

ओडीओपी उत्पादों को 'लोकल से ग्लोबल' बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी टेक्स की है। इस विभाग जानकारी को निर्यातक किया गया है, यहां ओडीओपी उत्पादों की बात कर रही है। ऐसे ही यूपी को मुख्य सहयोग मार्केट देश में है। इसमें उत्तराखंड, दुबई, इटली, ब्रिटेन, चिली, कतार, सऊदी अरबों का उत्तरप्रदेश, मध्य, बेलारूस, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, मोरिशस, मुजफ्फरपुर, नाइजर, पेरू, स्पेन, अफगानिस्तान, इराक, मिस्रपुर, पाकर, जर्मनी, ग्रीस, इराक, अफगानिस्तान, इराक, ओडीओपी उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी टेक्स की है। इस विभाग जानकारी को निर्यातक किया गया है, यहां ओडीओपी उत्पादों की बात कर रही है। ऐसे ही यूपी को मुख्य सहयोग मार्केट देश में है। इसमें उत्तराखंड, दुबई, इटली, ब्रिटेन, चिली, कतार, सऊदी अरबों का उत्तरप्रदेश, मध्य, बेलारूस, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, मोरिशस, मुजफ्फरपुर, नाइजर, पेरू, स्पेन, अफगानिस्तान, इराक, मिस्रपुर, पाकर, जर्मनी, ग्रीस, इराक, अफगानिस्तान, इराक,

प्रदेश सरकार ने निर्यातकों को जनहित एवं आवश्यकता के हेतु प्रोत्साहन योजना 2021-22 में प्रदेश के निर्यातकों को एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट, यूनिट सपोर्ट और कन्सल्टेंसी फीस, टेक्नोलॉजी एण्ड अनिल मशीनरी अपग्रेडेशन सपोर्ट, मार्केटिंग, मार्क, विदेश प्रोत्साहन, कुशलता सहायता, अधिकारपत्र सहायता, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रतिभाग करना तथा है। इस विभाग में ये यूपी इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स ने प्रदेश की निर्यातक इकाइयों को उपलब्धि सुविधाएं भी उपलब्ध की गयी हैं।

वैभवल और उद्यमिता का सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उद्यमियों के बीच व्यवसाय प्रतियोगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बाकर-स्वरूप का पुरस्कार और सम्मान प्रदान करते रहते हैं। दिसम्बर, 2022 में भी लगभग 10 उद्यमियों को विभिन्न उत्कृष्टता पुरस्कार तथा 10 उद्यमियों को व्यवसायगत सम्मान दिया। [illegible] पुरस्कार के सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए

एमएसएमई क्षेत्र में फूंकी जान

अतुलरंजन सिंह

वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में एमएसएमई का क्षेत्र दुर्दशा का शिकार था। [illegible] 13.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2017 से प्रदेश की निर्यातोन्मुखी योजनाओं के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दिया 24 जनवरी, 2018 को राज्य की पहली 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नया मार्ग खोल दिया गया है। [illegible] में प्रदेश की योजनाओं का 2.1 प्रतिशत है।

एमएसएमई [illegible] इकाइयों, कारीगरों और उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य यूपी को उद्यमशीलता की नगरी और उद्योग एक सुदृढ़ देने में प्रदेश सरकार ने भी भरपूर सहायता की। इस दी में बनाये 25 जिलों में ओडीओपी पुरस्कार बना मेलों में 'उत्पादकों वैश्विक सुदृढ़ कार्यक्रम', 'उत्पादकों यूपी योजना', मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना', 'एक जनपद एक उत्पाद जिला योजना योजना' आदि के 1 लाख 42 हजार लाभार्थी उद्यमियों, कारीगरों एवं व्यक्तियों को 10 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के एमएसएमई को मुख्यमंत्री प्रदान करते हुए

उद्यमियों को भरपूर प्रोत्साहन

- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 1,40,412 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 1.98 लाख प्रशिक्षितियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 10 हजार रुपये के ऋण वितरण किये जो रहे हैं।
- वर्ष 2021-19 के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना प्रारम्भ की गयी है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत 14856 युवाओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें योजना के 1,18,804 आवेदन मुद्रित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 17019 युवाओं को लाभान्वित किया गया, जिसमें योजना के 147452 आवेदनों का सृजन हुआ।

स्वदेशी को सम्मान

- वीर उधम आजादियों भारतीयों के सम्मान को बरकरार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बना उत्तर प्रदेश।
- 4212 लाभार्थियों को योजना बराबर वितरित करते हुए 8384 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया।
- मुख्यमंत्री खादी वस्त्र रोजगार योजनान्तर्गत 220 इकाइयों को लाभान्वित कर 2024 व्यक्तियों को रोजगार।
- मुख्यमंत्री आवेदक रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 4216 इकाइयों स्थापित एवं 8286 लोगों को रोजगार।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 17119 इकाइयों स्थापित एवं 1,79,286 लोगों को रोजगार।
- खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के अधिकारियों परिवारों अनेकता एवं 32 हजार किसानों एवं 10 उत्पाद किसी रोजगार प्रदान।

सौजन्य: सोशल इंजीनियरिंग